(b) whether it is also a fact that many representations have been made to Government to get the slaughter house shifted;

(c) whether it is also a fact that a new alternative site had been offered for the slaughter house about a year ago but no progress has been made in this regard; and

(d) by when it is likely to be shifted?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) No slaughter house exists on the Ring Road. However, there is one carcass utilisation centre in Pitampura along the Ring Road. There have been complaints of foul smell emitted by this Centre.

(b) Some representations have been received by DDA & MCD.

(c) and (d) DDA has reported that construction of a structure for the carcass centre was started in the north of road No. 50 about 1 k.m. away from the Village Burari. The construction was stopped on account of the objections raised by the residents of the area. A decision has been taken by the Delhi Administration for shifting carcass Centre alongwith the project of construction of a new Meat Processing Plant. The carcass Centre is likely to be shifted within two years.

Repairing of newly built flats by D.D.A.

2084. SHRIMATI MONIKA DAS: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state the names of the colonies where the Delhi Development Authority propose to undertake the work of repairing of newly built unoccupied flats?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): Repairs/rectification of defects in the flats wherever required are undertaken while the houses are under construction by the contractors and in the event of their failure such repairs are carried out at their risk and cost at the time of release of flats for allotment. No specific colonies are selected for undertaking such repairs.

मंत्रिपरिषद के भूतपूर्व सदस्यों के विरुद्ध लाइसेंस की आदि का बकाया

2085. **श्री सत्यप्रकाश मालवीय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980–84 की अवधि के दौरान की मंत्रिपरिषद के किन-किन भूतपूर्व सदस्यों पर आवास का किराया, बिजली प्रभार, पानी और टेलीफोन तथा अन्य सरकारी धनराशि बकाया है ; और

(ख) बकाया धनराशि के अब तक वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा माननीय सदस्य को प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली में कनिष्ठ अभियन्ताओं को क्वार्टरों का आबंटन

2086. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० आई० जैड क्षेत्र कालीबाड़ी मार्ग के जे, के, और एच ब्लाकों में कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रत्येक ब्लाक में दो क्वार्टरों का आबंटन किया गया है ; यदि हां तो क्या इन क्वार्टरों का आबंटन सम्पदा निदेशालय द्वारा अवधारित प्राथमिकता के आधार पर किया गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त क्वार्टरों के आबंटितियों को मकान किराया भत्ता भी दिया जा रहा है और उनसे कोई लाइसेंस फी भी नहीं ली जा रही है, यदि हां तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि "जे" ब्लाक आवासीय क्वार्टरों में वहां कार्यरत कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक अलग सेवा-केन्द्र का निर्माण किया गया है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) : (क) जी नहीं । तथापि, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत स्टाफ के लिये निर्धारित क्वार्टरों में से टाइप–1 का एक क्वार्टर कनिष्ठ इंजीनियर को आबंटित किया गया है । इसलिए अग्रता का आधार निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

Educated unemployed

2087. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of educated unemployed persons on the live registers of employment exchanges in the country as on the 30th June, 1985;

(b) whether any programme has been chalked out to provide more jobs to the unemployed persons; and

(c) if so, the extra funds allocated for the purpose?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) The latest available number of educated (Matric and-above) jobseekers, all of whom are not necessarily unemployed who were on the live registers of Employment Exchanges as on 31-12-1984 was 125.4 lakhs.

(b) During the Seventh Five Year Plan, employment is to be treated as a direct focal point of policy. The plan will have a National Employment Programme which will cover target groups, including the educated unemployed. The generation of gainful employment through integration of sectoral production plans with employment plans and enlargement of ongoing employment programmes would also be emphasised. In addition, Schemes will continue for promoting self-employment in economically viable activities backed up by the requisite training credit, marketing and organsational linkages.

(c) According to available information, the total allocation is the central sector for 1985-86 for Integrated Rural Development Programme (IRDP), Training of Rural Youth for Self-Employment Programme (TRYSEM), National Rural Development Programme (NREP), Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) and scheme for providing self-employment to Educated Unemployed Youth is Rs. 1010 crores.

मध्य प्रदेश में किसानों को खराब पम्पसैटों की सप्लाई

2088. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 3 मई, 1985 के अपने पत्र द्वारा मध्य प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को एम० यू० आई० कम्पनी द्वारा खराब पम्पसैट देने के संबंध में शिकायत की थी और उसकी जांच कराने की मांग की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां । श्री हुकमदेव नारायण यादव, संसद सदस्य राज्य सभा से दिनांक 3 मई, 1985 को लिखी केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Construction of drains in Pitampura, Delhi

2089. SHRI PYARELAL KHANDELWAL:
SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether construction of drains in Pitampura, in Delhi-North zone, were to